

## श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश

518 न्यू मोती बंगला, एम.जी. रोड, इन्दौर & 452007

Phone: 0731-2432822, Fax : 0731-2536600

Email : lcmpenf@mp.gov.in Website :http://labour.mponline.gov.in

क्रमांक: 227/ऑफ ला./नवम/प्रवर्तन/2025/ 5286

इन्दौर, दिनांक 02/03/26

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष/मण्डल/निगम/प्राधिकरण प्रमुख, मध्य प्रदेश

विषय: विभागों/मण्डलों/निगमों द्वारा ठेका श्रमिक/आउटसोर्स कर्मचारियों के नियोजन में वैधानिक पंजीयन एवं लाइसेंस संबंधी प्रावधानों के पालन के संबंध में।

विगत अवधि में यह अवलोकन में आया है कि विभिन्न शासकीय विभागों, मण्डलों, निगमों एवं विशेषतः निर्माण कार्य संपादित करने वाले संस्थानों द्वारा ठेका श्रमिकों एवं आउटसोर्स कर्मचारियों का नियोजन ठेकेदार/एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है।

कुछ प्रकरणों में यह भी पाया गया है कि प्रमुख नियोजक के रूप में पंजीयन तथा संबंधित ठेकेदारों द्वारा वैधानिक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया समय पर पूर्ण नहीं हो पाती है। यह स्थिति मुख्यतः प्रक्रियात्मक जानकारी के अभाव अथवा कार्यदेश की सूचना श्रम कार्यालय को समय पर उपलब्ध न होने के कारण उत्पन्न होती है।

उक्त संदर्भ में प्रचलित वैधानिक प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना अपेक्षित है।

### 1. प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान

(क) संविदा श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970

धारा 7 – प्रत्येक प्रतिष्ठान, जहाँ 50 या उससे अधिक ठेका श्रमिक नियोजित हों अथवा पूर्ववर्ती 12 माह में किसी भी दिन नियोजित रहे हों, वहाँ प्रमुख नियोजक द्वारा पंजीयन कराना अपेक्षित है।

धारा 12 – कोई भी ठेकेदार, वैध लाइसेंस प्राप्त किए बिना, ठेका श्रमिक नियोजित नहीं कर सकता।

धारा 23 – पंजीयन/लाइसेंस के अभाव में ठेका श्रमिक नियोजन दंडनीय है।

(ख) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020

धारा 47 – संविदा श्रमिकों के नियोजन हेतु लाइसेंस संबंधी प्रावधान।

धारा 03 – प्रमुख नियोजक का पंजीयन।

धारा 92 से 96 एवं 114 – उल्लंघन की दशा में दंड एवं प्रशमन का प्रावधान।

उक्त कोड के अंतर्गत एकीकृत/पोर्टल आधारित पंजीयन एवं लाइसेंस प्रणाली का प्रावधान है। नियम पूर्ण रूप से प्रभावी होने तक, संबंधित पूर्व प्रावधान लागू रहेंगे।

